(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आयुक्त का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या आयुक्त की नियुक्ति न होने से संगठन का कार्य प्रभावित हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यह पद कब से खाली पड़ा है और संगठन का कार्य सुचारू रुप से चलाने के लिए यह नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा.मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त का पद 16.5.1998 को रिक्त हुआ। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र उक्त तारीख से उस पद का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे हैं। पद को भरने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरु कर दी गई हैं।

भीरतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव

3468. **श्री रामगोपाल यादव**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेलों विशेषकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सारे निर्णय राजनीति से प्रेरित, स्वार्थ एवं ईर्ष्या की भावना से लिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो इसकी समयावधि क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय क्रिकेट संघ को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने हेतु सरकार क्या भूमिका अदा करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) भारत में क्रिकेट संधों का राष्ट्रीय स्तर का एक खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। बी.सी.सी.आई. एक स्वायत्तशासी संगठन है और इसका गठन इसके निजी अपनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंधों के आंतरिक कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है।

Financial Assistance to Balwadis and Anganwadis

3469. SHRI J. CHITHARANJAN: SHRI GAYA SINGH:

WiU the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Human Resource Development Ministry have issued any order stopping financial assistance given to balwadis and to reduce tjie number of anganwadis in each block;

(b) if so, the details of the order in this regard; and

(c) what is the number of balwadis and anganwadis in operation at present in kerala?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) It was contemplated to phase out the Balwadis sanctioned under Balwadi Nutrition Programme with effect from 1.4.98. The scheme of Balwadi Nutrition Programme has now been continued till 31.3.2001 in the areas not covered by ICDS Projects. No instructions have been issued to reduce the number of anganwadis in any ICDS Project.

(a) Does not arise.

(b) At present 181 Balwadis and 20123 Anganwadis are in operation in Kerala.

Criteria for Creation of Posts of Vice-Principals in Navodaya Vidyalayas

3470. SHRI RAGHAVJI:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(b) the criteria for creation of posts of Vice-Principals in Navodaya Vidyalayas;

(c) the number of posts of Vice-Principals created as yet; details thereof, Vidyalaya-wise;

(a) the modus opcrandi of filling up these posts; and

(b) the details of posts of Vice-Principals wlich have since been filled up and which arc vacant?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) The post of Vice-Principal is sanctioned to a Navodaya Vidyalaya functioning at +2 stage having not less then 350 students in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 (Revised).

(b) 137 posts of Vice-principals have been created till July, 1997. Vidyalaya-wise details arc being ascertained.

(c) As per Recruitment Rules the posts of Vice-Principal arc filled up 1007.. by promotion by selection from Post Graduate Teachers having 5 years regular service in the Grade, failing which by transfer on deputation.

(d) The Hon'ble High Court of Jammu & Kashmir at Jammu in the Civil Writ Petition No. 293/95 has stayed the operation of seniority list of Post Graduate Teachers issued by the Samiti till the final disposal of the petition. Hence the post of Vice-Principal could not be filled up in any of the Navodaya Vidyalayas since May 95.

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च द्वारा विद्यालयों की आवश्यकता के लिए किया गया आकलन

3471. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**:

श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में यूनिवर्सल एलीमेन्ट्री एजूकेशन के लिए स्कूलों की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च ने 26,424 करोड़ रु. की जरुरत आंकी है;

(ख) यदि हां, तो इस आकलन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा केवल 9,5000 करोड़ रु. का ही आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यूनिवर्सल एजूकेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष राशि को क्या व्यवस्था है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत में स्कूल स्तर पर प्रासंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 26424 करोड़ रु. की आवश्यकता का आकलन किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा संबंधी कार्य दल ने नौंवीं योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 79260 करोड़ तथा राज्य क्षेत्र में 46393 करोड़ रु. के अनन्तिम परिव्यय की सिफारिश की है। अनन्तिम शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1995-96 में शिक्षा के राजस्व लेखा में संपूर्ण शिक्षा के लिए 5068 करोड़ रु. योजनागत तथा 26760 करोड़ रु. योजनेतर का बजट व्यय था। विश्लेषण के रूझान से पता चला है कि प्रारंभिक शिक्षा पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र के शिक्षा संबंधी राजस्व लेखा के कुल व्यय का 40-50 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 1998-99 के 4225 करोड़ रु. के कुल शिक्षा बजट में प्रारंभिक शिक्षा का केन्द्रीय योजनागत परिव्यय 2778 करोड़ रु. है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए निधि का आवंटित किया जाना ससाधनों की उपलब्धता तथा राज्यों द्वारा उनकी उपयोगिता पर निर्भर करता है।

SAARC Convention on Prevention and Combatiug Traffickng in Women and Children

3472. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(c) whether India hosted recently Expert Group meeting on SAARC convention on Prevention and Combating Trafficking in Women and Children in New Delhi, as reported in the Hindustan Times dated 19th June, 1998;

(d) if, so, what decisions were taken within and between SAARC countries to coordinate their efforts and take effective measures to address this problem; and